मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की सूची में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं, जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वे फसल की असफलता के जोखिम से बच सकें।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना किसानों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। वह मखाना बोर्ड संबंधित आर एंड डी पर काम करेगी, नई मखाना खेती तकनीकों को विकसित करेगी, किसानों को उद्योग से जोड़ेगी और एफबीओ के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और निर्यात के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा यह ट्रेड फेयर, ब्रांडिंग, स्टोरेज और देश विदेश में मखाना को प्रमोट करने का काम करेगी। हम आदरणीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि वे अभी मॉरीशस गए थे और वहां जाकर उन्होंने वहां के प्रधान मंत्री को मखाना ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Kumar Jha: Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

माननीय श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, "Concern over the problem of unauthorized parking near Supreme Court, Delhi High Court & Patiala House Court."

Concern over the problem of unauthorized parking near Supreme Court, Delhi High Court and Patiala House Court.

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (उत्तर प्रदेश) **:** सर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिया गेट का जो सर्कल है, वहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट स्थित हैं। वहां तमाम वकीलों और तमाम मुवक्किलों, जो मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए पार्किंग की कोई जगह नहीं है। इंडिया गेट एक टूरिस्ट स्पॉट है और एक हाई सिक्योरिटी जोन भी है। वहां पार्किंग के लिए जगह न होने के कारण वकीलों को गाड़ी पार्क करने में बहुत दिक्कत आती है। वहां अपना केस लड़ने के लिए मुवक्किल भी आते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट बिल्कुल सर्किल पर स्थित है। वकील वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके समय पर अपना केस लड़ने नहीं पहुंच पाते हैं। वह एक हाई सिक्योरिटी जोन है। वहां वकीलों को बहुत परेशानी होती है। पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए वहां पर एक डेजिग्नेटिड पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां इतनी गाड़ियां आती हैं और जब वे सड़क पर पार्क होती हैं, तो इससे उनको तकलीफ होती है। इसके साथ ही वह एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए बाहर से तमाम लोग आते हैं, उनके लिए वहां जाम की स्थिति बन जाती है। वह एक सिक्योरिटी जोन भी है।

इन तीनों कोर्ट्स के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस होना चाहिए, जहां से फेरी चले और वकीलों को समय पर कोर्ट्स में पहुंचने में कोई दिक्कत न आए और जो मुवक्किल अपने मुकदमे लड़ने आते हैं, उनको भी कोई दिक्कत न आए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Kunwar Ratanjeet Pratap Narayan Singh: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, "Need to address the problem of water in Morni Hills, Haryana."

Need to address the problem of water in Morni Hills, Haryana.

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे हरियाणा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरियाणा राज्य में पथरीली जमीन की तरफ जो पहाड़ी इलाका पड़ता है, खासकर वहां पर ग्राउंडवाटर रिसोर्स की बहुत समस्याएं रहती हैं, जो कि खासकर पंचकूला, कालका, मोरनी हिल्स क्षेत्र के अंदर है। मैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही हरियाणा सरकार की मेहनत की भी सराहना करता हूं, जो कालका, मोरनी हिल्स क्षेत्र अंबाला और पंचकूला जैसे इलाकों में पीने के पानी, खेती, उद्योगों और अन्य चीज़ों के लिए जहां पानी की आवश्यकता है, उसके लिए काम कर रही है।

महोदय, मैं सदन का ध्यान इस चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी, वैसे तो राज्य का विषय है और हरियाणा ने उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने का काम किया है, लेकिन पानी के जो स्रोत हैं, चाहे उनकी जो schematics हैं, जहां नक्शा बनने की बात हो, कमी वाले इलाकों को चिन्हित करने की बात हो, योजना तैयार करने की बात हो, इन सब चीजों को लेकर वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही काम हो सकता है। यहां पर जटिल परिस्थितियां होने की वजह से, जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी की वजह से ये परिस्थितियों और कठिन बन जाती हैं। उनकी जो दिक्कतें और समस्याएं हैं, खासकर जो पहाड़ी इलाकें हैं, वहां किसानों को अधिक दिक्कतें आती हैं।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से हरियाणा सरकार के अधिक सहयोग की उम्मीद रखता हूं, ताकि जो क्षेत्र वंचित रह गए हैं, उन तक भी पानी पहुंच सके, चाहे वह किसानों के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार की पहल के साथ मिला देने से हमारे जो funds हैं, उनको dovetail किया जा सकता है, ताकि जिस मंशा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं और अगर कहीं उसमें कमी रह रही है, तो उसको पूरा किया जा सके।